नए जंगी संग्राम की ओर बढ़ो

बी० टी० रणदिवे
सभापति, सी० आई० टी० यू०

विशाखापत्तन में सी आई टी यू की जनरल कौंसिल की सभा
४ से ७ अप्रैल, १९७४ में दिया गया उद्घाटन भाषण

सी आई टी यू प्रकाशन

मूल्य—पचास पैसे

सी आई टी यू की ओर से सेक्रेटरी एम० के० पन्धे द्वारा प्रकाशित और प्रेसमैन, ६, नवीन पाल लेन, कलकत्ता-६ से मुद्रित।

नये जंगी संघर्षों के लिये आगे बढ़ो

कामरेड,

हम एर्नाकुलम सम्मेलन के एक वर्ष बाद मिल रहे हैं। बिलम्ब का कारण आपको मालूम है। इसीलिये मैं उसकी चर्चा करना नहीं चाहता।

शुरू में मैं, आप सबकी ओर से, हमारे प्रिय कामरेड मुजफ्फर अहमद को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। का० मुजफ्फर अहमद कम्युनिस्ट आन्दोलन के महान नेता थे तथा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मा०) की केन्द्रीय कमेटी के सदस्य और हमारे ट्रेड यूनियन आन्दोलन के एक निर्माता तथा किसान आन्दोलन के संस्थापक थे।

मैं उन सबको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने हाल की लड़ाईयों में मजदूर वर्ग की ओर से लड़ते हुए अपनी जान दे दी।

कामरेड, संकटकाल का हमारे आन्दोलन पर आक्रमण करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेसी जेलों में हजारों लोगों को उनपर बिना मुकदमा चलाए या किसी भी प्रकार के अपराध का अभियोग लगाये, बिना केस चलाए नजरबंद रखा जा रहा है। हमारा संगठन संकटकाल को खत्म करने और सभी राजनीतिक बन्दियों की रिहाई की मांग करता है।

आप सबकी ओर से मैं पश्चिम बंगाल में हमारी ट्रेड यूनियनों पर चल रहे गुण्डों के आक्रमणों के प्रतिवाद में, अपनी आवाज उठाता हूं। हमारे कार्यालयों पर अब भी वे जबरन कब्जा जमाए हुए हैं। सैकड़ों मजदूरों को अपने काम पर जाकर जीविकोपार्जन से रोका जा रहा हैं। समूचे ट्रेड यूनियन आन्दोलन को निश्चितरूप से सरकार

समर्थित गुण्डागर्दी को समाप्त करने की माँग करनी चाहिए तथा पश्चिम बंगाल में फिर ट्रेड यूनियन की स्वाधीनता को कायम करने की आवाज उठानी चाहिए।

कामरेड, आप सभी वियतनाम के ट्रेड यूनियन फेडरेशन की तीसरी कांग्रेस में उपस्थित होने के निमन्त्रण के बारे मे जानते हैं तथा यह भी जानते हैं कि हमारे संगठन के प्रतिनिधित्व के लिए मुझे नियुक्त किया गया था। मैंने उस सम्मेलन के विषय में हमारे "वर्किंग क्लास" में लिखा है। हनोई में मैंने क्या देखा, उसकी एक रिपोर्ट भी मैं वितरित कर रहा हूँ। मुझे बिश्वास है कि जनरल कौंसिल इस निमन्त्रण के लिए धन्यवाद देगा तथा फेडरेशन के नाम यह कामना करते हुए एक बन्धुत्वपूर्ण हार्दिक संदेश भेजेगा कि समाजवादी उत्तर वियतनाम के निर्माण के लिए वियतनाम को पूरी तरह स्वाधीन करने तथा समाजवादी औद्योगीकरण के काम मे अपनी अगुआ भूमिका को पूरा करने के संघर्ष में उसे सफलता मिले।

नई परिस्थिति

कामरेड, पिछले सम्मेलन में हमारी बैठक के बाद से अन्तर्राष्ट्रीय तसवीर में मजदूर वर्ग के पक्ष में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। पेरिस सन्धि से, जिस पर उसी समय हस्ताक्षर किये गये थे, न सिर्फ अमरीकी साम्राज्यवाद की ही एक बड़ी पराजय हुई के बल्कि यह संधि पूँजीवाद के गहरे होते हुए आम संकट से पैदा हुई विस्फोटक आर्थिक स्थिति के बीच हुई थी। मुद्राओं का अवमूल्यन तथा सबसे ऊपर, डालर का अवमूल्यन, मुद्रा युद्ध, बाजार हथियाने के लुटेरू प्रयास, भुगतान संतुलन की कठिनाई, तथा अन्त में आर्थिक स्थिरता के बीच बढ़ती हुई मुद्रास्फीति—ये सब वियतनाम छोड़ कर अमरीकियों के भागने के समय तक सामने आ चुके थे, पिछले वर्ष में और गहरे होते रहे हैं। उससे पूँजीवादी व्यवस्था की अस्थिरता और

उसका दिवालियापन नंगा हुआ है जिससे पूँजीवादी दुनिया में व्यापक तौर पर मजदूर वर्ग के संघर्ष फैले हैं।

पिछले वर्ष जापान मे गुजरबसर के खर्च मे २० सैकड़ा वृद्धि हुई है, ब्रिटेन में मुद्रास्फीति की दर १२ सैकड़ा रही है। ऐसा अनुमान है कि १९७४ में उस दर में और १५ सैकड़ा की वृद्धि होगी। व्यापार संतुलन में आज तकके सब से अधिक घाटे २३ करोड़ ४० लाख के साथ एक वर्ष में खाद्य के दामों मे २० सैकड़ा वृद्धि हुई है। अमरीका में पिछले वर्ष उपभोक्ता सामग्री के दामों ९·४ प्रतिशत वृद्धि हुई है। यह पिछले दो दशकों मे सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि है। १९७४ मे खाद्य के दामों में ८ से १६ प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जबकि खाद्यान्न, पावरोटी, केक इत्यादि के दाम में २० सैकड़ा तक की वृद्धि हो सकती है।

इटली, पश्चिम जर्मनी इत्यादि में भी इसी प्रकार के रुझान दिखाई देते हैं। पश्चिम जर्मनी में जनवरी महीने में रोटी का दाम ८ सैकड़ा बढ़ गया तथा वनस्पति का दाम १६ सैकड़ा बढ़ा। गुजरबसर के खर्च का सूचकांक एक महीने मे १०·३ सैकड़ा बढ़ गया। इसके परिणाम-स्वरूप वेतन में हुई वृद्धि शून्य हो गयी। फ्रांस में भी स्थिति कोई बेहतर नहीं है। २१ मार्च को फ्रांस के अर्थमन्त्री को यह कह कर कुछ मुद्रा-स्फीति विरोधी कदमों की घोषणा करनी पड़ी कि आर्थिक परिस्थिति जितना विश्वास किया गया था, जितना सोचा गया था, उससे कहीं अधिक खराब है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष देश के राष्ट्रीय उत्पादन दर पिछले वर्ष की ६·६ सैकड़ा से घटकर ३·६ प्रतिशत हो जायेगी। भुगतान संतुलन में आनेवाली घटती अनुमानतः ३६० करोड़ डालर होगी। फ्रांस में मुद्रा-स्फीति की वार्षिक दर १८ प्रतिशत कूती गयी है। फ्रांस के प्रधानमन्त्री ने यह स्वीकार किया है कि नये कदमों से फ्रांस के जीवन स्तर पर गहरा असर पड़ेगा।

बढ़ति बेरोजगारी

अमरीका में औद्योगिक उत्पादन दिसम्बर और जनवरी महीने में गिरा है। पिछले महीने इसमें ८ प्रतिशत की गिरावट आई है। बेरोजगारी बढ़ रही है तथा उर्जा संकट से और अधिक गहरी हो रही है। बेरोजगारों की संख्या ५० लाख से अधिक है।

आर्थिक मंदी की वजह से बेरोजगारी की दर ५.२ प्रतिशत पहुँच गयी है तथा श्रम विभाग के प्रवक्ता के अनुसार उर्जा संकट के कारण और ५ लाख बेरोजगार बढ़ सकते हैं।

पश्चिम जर्मनी मे लगभग ५ लाख लोग दिसम्बर के अन्त में बेरोजगार थे। अर्थमन्त्री ने यह अनुमान लगाया है कि इस वर्ष यह संख्या और अधिक बढ़ेगी तथा "बेरोजगारी के खिलाफ हमेशा से अधिक लड़ाई करनी होगी।" इटली में बेरोजगारों की संख्या १० लाख के ऊपर पहुँच गयी है तथा उत्तरी यूरोप के देशों में भी यह संख्या बढ़ रही है।

इन देशों में हड़तालें अवश्यम्भावी रूप से बढ़ रही हैं। वेतन वृद्धि पर रोक तथा संकट के बोझ को मजदूरों पर लादने के प्रयास के खिलाफ ब्रिटेन के खान मजदूरों के बहादुराना संघर्ष ने ब्रिटेन में टोरी सरकार को खतम कर दिया। पश्चिम जर्मनी के इतिहास में पहली बार फरवरी महीने में सरकारी कर्मचारियों, डाक मजदूर तथा उनके साथही रेल मजदूरों ने हड़ताल की। अढ़ाई लाख मजदूरों ने उस सरकार का सामना किया जिसे उन्होंने चुना था तथा सरकार को वेतन में ११ सैकड़ा वृद्धि के लिए वाध्य कर दिया। पिछले वर्ष के शुरू के वक्त इटली में २ करोड़ मजदूरों ने हड़ताल की। इस वर्ष २१ मार्च को पैरिस में हड़ताल करनेवालों ने बंक, रेलवे तथा हवाई सेवाओं को अस्त-व्यस्त कर दिया, दुकानों और आफिसों को बन्द कर दिया, पूरे पैरिस में यातायात को बिल्कुल ठप्प कर दिया। यह

आन्दोलन बढ़ रहे दामों के निराकरण के लिए, अधिक वेतन की सर्वव्यापी मांग को लेकर था। सरकार के "मुद्रा-स्फीति विरोधी" नए कदमों को "मजदूरों के खिलाफ आक्रमण की घोषणा के समान" तथा "मुद्रा-स्फीति विरोधी योजना नहीं बल्कि वेतन विरोधी योजना" बताकर उनकी निन्दा की गयी।

पूँजीवाद के आम संकट से बढ़ रही इस चरमराहट ने १९३० की महान मंदी की याद दिला दी है तथा इसने विश्व बंक के भूतपूर्व प्रधान अर्थशास्त्री आर्विंग फ्रैडमैन से यह कहलवा दिया कि "मैं इन विचारों का विरोध नहीं कर सकता कि मौजूदा प्रक्रिया की एक स्वाभाविक परिणति विश्वव्यापी दर वृद्धि में होगी। इसीसे ढह जाने का विश्वास जन्म लेता है। उत्पादन के औजारों में लगनेवाली समूची पूँजी सोने या खाद्य में लग जायेगी और एक छिपी हुई विश्व-व्यापी मन्दी जन्म लेगी।

वाटरगेट कांड

सिर्फ अर्थ व्यवस्था की नींव ही चरमरा रही हो ऐसी बात नहीं है। पूँजीवाद के गढ़ अमरीका में निक्सन-कांड के साथ ही इसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा में भी तनाव चरम पर पहुँच गया है।

आज दुनिया भर की आँख वाटरगेट-कांड तथा उन अपराधों पर गड़ी हुई है जिसमें अमरीकी राष्ट्रपति और उसके सभी अनुचर एक के बाद एक अपराधों के लिए अपराधी हैं। उन्होंने व्यक्ति स्वतंत्रता की हत्या की। अपने आलोचकों के खिलाफ अभियोग लगाने का मसाला जुटाने के लिए चोरियाँ कीं, घरों पर हमले किये। कालाबाजारी करने के लिए मसाला जुटाने के लिए उन्होंने विरोधी दलों में जासूसों भेजे। चुनाव के लिए गौरकानूनी तरीके से रुपए बटोरे तथा गलत हिसाब पेश किया।

मानो अपराधों की यह सूची नाकाफी थी, निक्सन ने कम्बोडिया के खिलाफ चोरी-छिपे युद्ध छेड़ कर इसे चरम पर पहुंचा दिया। अपने इस कारनामे को उसने संसद से छिपाया। तथा बमबारी का झूठा लेखा-जोखा पेश किया जिससे कांग्रेस और सीनेट को बिल्कुल धोखा दिया गया। इस प्रकार अमरीकी जनतंत्र में न जनता और न कांग्रेस को दूसरे देशके खिलाफ युद्ध के बारे में हाँ-ना करने का वास्तविक अधिकार प्राप्त है। लेनिन ने कितना सही कहा था—"अमरीका से स्वीटजरलैंड तक किसी भी देश को लिया जाए···इन देशो में 'राज्य' के वास्तविक काम पर्दे के पीछे होते हैं तथा ये विभागों, अर्थ मंत्रालयों तथा फौजके आफसरों द्वारा किये जाते हैं। पार्लियामेंट को आम जनता को बेवकूफ बनाने की बातें करने के लिए छोड़ दिया गया है।" वाटरगेट-कांड से यह फिर साफ हो गया है कि राष्ट्रपति और उसके विदेश विभाग की सेवा में फौजी विभाग ने जासूसी की है।

अन्दरूनी झगड़ा

साम्राज्यवाद के तीन केन्द्र—ईईसी (यूरोपीय अर्थ सम्प्रदाय), अमरीका तथा जापान के बीच गहरे आर्थिक झगड़े शुरू हो गये हैं। ईईसी के देशों में भी अन्तर्विरोध बढ़ रहे हैं।

तेल संकट ने सभी साम्राज्यवादी हिस्सेदारों के बीच अन्तर्विरोध को तीखा कर दिया है। यह विशेष कर अमरीका के आह्वान पर हुए तेल सम्मेलन के दौरान प्रगट हुआ।

फ्रांस और ईईसी के अन्य सदस्यों के बीच संघर्ष इतना तीखा था कि बुर्जुआ अखबारों को इस बात का डर लगने लगा कि सम्प्रदाय जिन्दा भी रहेगा या नहीं। किन्तु मध्यपूर्व एशिया के खिलाफ एक ब्लाक में यूरोप को शामिल करने तथा तेल उत्पादक और तेल की

खपतवाले देशों के बीच सीधे व्यापार को बन्द करने का अमरीकी प्रयास सफल होता नजर नहीं आता है और इस प्रकार के व्यापार पर रोक लगानेवाले नियम-कानूनों को रद्द कर देना पड़ा।

यूरोप को अपने बस में करने में विफल हो जाने से ही १६ मार्च को निक्सन की धमकी भरी बौखलाहट सामने आई। उसने यूरोपीय देशों को अपनी सभी यात्राओं को रद्द कर दिया। "यूरोपीय देशों को दोनों ओर से लाभ नहीं मिल सकता। सुरक्षा के मोर्चे पर वे अमरीका की भागीदारी और सहयोग तथा आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर संघर्ष और यहाँ तककि शत्रुता के लिए पैर बढ़ाना—यह नहीं चल सकता।"

जहाँ इन घटनाओं से पूँजीवादी देशों में तीखे हो रहे वर्ग संघर्ष, राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम में तेजी (अरबदेश), पूँजीवादी देशों की सरकारों का उखड़ना (ब्रिटेन) सामने आता है वहीं इनसे बदल रही परिस्थितियों पर अपनी पकड़ कायम रखने के लिए चल रही अमरीकी साम्राज्यवादियों तथा अन्यों की करतूतें भी देखने को मिलती हैं।

सहयोग

लगातार बढ़ती हुई आर्थिक प्रतिद्वन्द्विता से इनके बीच विदेश नीति सहित एक बिराट क्षेत्र में अन्तर्विरोध बढ़ रहे हैं। प्रत्येक देश समाजवादी देशों से सम्बन्ध बढ़ाने के अपने तरीके को विकसित करना चाहता है। अमरीका और सोवियत संघ, अमरीका और जनवादी चीन के बीच सन्धियाँ काफी महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं। इन्हें समाजवादी दुनिया की बढ़ी शक्ति, बढ़ रहे राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम, साम्राज्यवादी खेमे की कमजोरी तथा उसकी यह आशा कि इससे साम्राज्यवादियों को अन्यत्र अपनी आक्रामक कार्रवाइयों में मदद मिलेगी और समाजवादी खेमे के मतविरोधों का वे लाभ उठा सकेंगे

इत्यादि—से साम्राज्यवादी कौशलों में आये परिवर्तन के रूप मे समझा जा सकता हौ बर्लिन पर सयझौता, पिछले युद्ध से बनी सीमाओं की स्वीकृति—ये महत्वपूर्ण घटनाएँ है। किन्तु इस प्रकार की तमाम बातें कि इन घटनाओं शुरुआत हुई है, भ्रामक हैं और वस्तुतः इनसे साम्राज्यवादी कारस्तानियों को छिपाने में मदद मिलती है।

न्हान दान (उत्तरी वियतनाम के अखबार) ने सही लिखा था कि "साम्राज्यवादी दुनिया के कुछ बड़े देशों से इसीलिए सन्धि की नीति अपनाते हैं ताकि वे अपनी शक्तियों को बटोर कर दुनिया के क्रान्तिकारी आन्दोलनों का विरोध कर सकें। खुद अपने देशों में क्रान्तिको कुचल सकें तथा नये युद्ध की तैयारियाँ करते हुए राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों का नाश कर सकें।"

इसीलिए हमें एआईटीयूसी के नेताओं जैसे संशोधनवादियों से सावधान रहना चाहिए जो यह प्रचार करते हैं कि हम अर्न्तराष्ट्रीय शान्तिपूर्ण विकास के काल में प्रवेश कर चुके हैं।

यदि चिली में सन्धि की बातें करनेवाले अमरीकी साम्राज्यवादियों की धिनौनी साजिशें सामने आई हैं तो अक्तूबर महीने में अरब राष्ट्रों और इसराइल के बीच हुए युद्ध से यह पता चलता है कि जनता की मुक्ति की अदम्य इच्छाओं के सामने यह अपनी कारस्तानियों लिए वाध्य हैं। तथा अपने मुवक्किल की रक्षा में वह सन्धि की तमाम बातें ठुकरा देते हैं। यह सीरिया में अबभी अड़ंगे डालने का खेल खेल रहा है।

तेल उत्पादक देशों द्वारा छेड़े गये तेल युद्ध ने साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष के एक और तरीके को सामने रखा है। यह है पहले के उपनिवेशों द्वारा अपने प्राकृतिक स्रोतों का मुख्य शक्ति के खिलाफ असरदार इस्तेमाल करके साम्राज्यवादी देशों में एक के बाद एक संकट पैदा करना।

कामरेड, इन स्थितियों को समझना जरूरी है क्यों कि इसके बिना हम न तो अपनी अन्तर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी को पूरा कर सकेंगे और न ही हम खुद अपने संघर्षों को सही दृष्टि से चला सकेंगे। हमारे आन्दोलन में यह रुझान देखने में आता है कि समाजवादी देशों की बड़ी आर्थिक उपलब्धियों का उल्लेख किए बिना हमारे संघर्ष चलाए जायें। क्या हमारे लिए यह गर्व की बात नहीं है कि जब समूची पूँजीवादी दुनिया मुद्रा बाढ़ की मार में जकड़ी हुई है, उसी समय समाजवादी अर्थव्यवस्था में महँगाई नाम की चीज नहीं है? हम यह भी भूल जाते हैं कि हमारा प्रधान शत्रु अमरीकी साम्राज्यवाद है—वह जो वियतनाम में जन-हत्या चलाता है, जो चिली में विद्रोह करवा कर सैकड़ों क्रान्तिकारियों की हत्या करवाता है। इस अन्तर्राष्ट्रीय शत्रु से उसकी सभी चालों का वस्तुतः पर्दाफाश करके तथा उन्हें नाकाम बना कर हमें अपनी धरती पर लड़ना होगा।

सक्रिय अमरीकी साम्राज्यवाद

अमरीकी साम्राज्यवाद ने इस उप-महाद्वीप में अपनी खो गई पहल को पुनः पाने के लिए शीघ्र कदम उठाए हैं। बंगलादेश में सहायता पहुँचा कर तथा बहुत ही दोस्ताने और सहयोगी होने का स्वांग रचके वह अपने प्रति नयी धारणा पैदा करना चाहता है। उसके दलाल भारत और बंगलादेश के बीच दुश्मनी के बीज बोने में लगे हुए हैं। बंगलादेश के कुछ प्रतिक्रियावादी खुलेआम वहाँ की सरकार द्वारा सोवियत संघ से दोस्ताना सम्बन्ध रखने पर आक्रमण तथा धार्मिक उग्रवाद को उकसा रहे हैं।

इसके साथ ही साथ अमरीकी सरकार ईरान के शाह को तथा फारसकी खाड़ी के अन्य शासकोंको फैंटम जेट और अत्याधुनिक शस्त्रों की उनकी सभी माँगों को पूरा करके काफी जोरों पर हथियारों

से लैस कर रही है। इसका लक्ष्य सोवियत प्रभाव के विरुद्ध है। इसका मकसद है अरब जनवादी शासनों की खिलाफत करना तथा पाकिस्तान के प्रतिक्रियावादी सैनिक गुट को उनके भारत विरोधी कामों में शह देना। एशियाई देश को एशियाई देश के खिलाफ लड़ाने का यह पुराना खेल जारी है। वह साथ ही साथ यह हिन्द महासागर के दोनों ओर अफ्रिकी किनारों से लेकर आष्ट्रेलिया तक के सैनिक अड्डों की पूरी श्रृंखला को मजबूत तथा पूरी कर रहा है, जैसा कि दियगो गार्सिया द्वीप तथा पाकिस्तान के करीब ईरान के अरब समुद्र के किनारे पर हवाई अड्डों पर कर रहा है।

इन सबसे भारत तथा इस उप-महाद्वीप की जनता की स्वतंत्रता पर खतरा है। दियगो गार्सिया पर अड्डा बनाने का कई देशों ने विरोध किया है किन्तु हमारे ट्रेड यूनियन आन्दोलन ने इस खतरे को अनदेखा किया है। हमारे देश की जनता तथा इस उप-महाद्वीप के मजदूर वर्ग के हितों में हमें इन अमरीकी साजिशों के खिलाफ तेज आवाज उठानी चाहिए तथा इनके खिलाफ अपने देश की जनता को जागृत करना चाहिए।

बंगलादेश को स्वीकृति

हमें खुशी है कि पाकिस्तान सरकार ने अन्त में बंगलादेश को स्वीकृति दे दी है। हम पाकिस्तान और बंगलादेश के मजदूर वर्ग को अपना दोस्ताना अभिनन्दन भेजते हैं और यह विश्वास जाहिर करते हैं तीनों देशों की जनता के बन्धुत्वपूर्ण सम्बन्धों के लिए। सर्वहारा की एकजुटता के लिए तथा उप-महाद्वीप में तनाव पैदा करने और एशियाई देशोंको एशियाई देशोंके खिलाफ लड़ाने की अमरीकी साम्राज्यवाद की चालों को पराजित करने के लिये तीनों देशों के सर्वहारा एकजुट होकर सक्रिय रहेंगे। आपस में ऐसी समझदारी तथा कार्रवाइयाँ जरूरी हैं क्योंकि स्थिति को गर्म बनाये रखने के लिए साम्राज्यवादी

और प्रतिक्रियावादी जुट चुके हैं। एक दूसरे के जनवाद तथा नागरिक स्वाधीनता के लिए संघर्षों का समर्थन करना हमारा परस्पर कर्त्तव्य है ताकि हमारे देश की विदेशी नीति के निर्धारण में जनता की आवाज छायी रहे।

बढ़ते संघर्ष

पिछले समूचे वर्ष में महँगाई, बेरोजगारी, अन्न की कमी की मार के खिलाफ विभिन्न स्थानों पर मजदूर वर्ग, हमारा सीआईटीयू तथा जनता ने जन-प्रतिवाद किये हैं। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाड़ू, त्रिपुरा तथा अन्य कई राज्यों में बढ़ते दामों तथा बेरोजगारी के खिलाफ अन्य संगठनों के साथ एकजुट होकर कई बड़े-बड़े बन्द संगठित किए गये। संगठित मजदूर वर्ग और कर्मचारियों के साथ ही अब जनता के सभी हिस्से सामने आ रहे हैं तथा व्यापक जनवादी संघर्ष के लिए एकजुट प्रतिवाद प्रारम्भ बिन्दु बन गया है। कई राज्यों मे व्यापक आधार पर महँगाई विरोधी कमेटियों का गठन किया जा रहा है जिनमें ट्रेड यूनियनें, राजनीतिक दल, कर्मचारियों, महिलाओं और छात्रों के संगठन भाग लेते हैं। उन राज्यों में जहाँ वामपंथी और जनवादी दल मजबूत नहीं है, वहाँ संगठित ट्रेड यूनियन आन्दोलन द्वारा की गई पहल में सरकारी नीतियों के खिलाफ जनता का प्रतिवाद संगठित होता है। यह आन्दोलन को दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी दलों द्वारा गलत रूप देने से रोकते हुए उसे एक जनवादी दिशा देता है।

कांग्रेस द्वारा लादी गयी भूख, महँगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ गुजरात की बहादुर जनता का शक्तिशाली संघर्ष तथा दो महीनों से भी अधिक समय तक इसका लगातार चलते रहना—इसने कांग्रेसी

शासन के खिलाफ जन-प्रतिरोध के शानदार पृष्ठों की रचना की है। यह जनता के लगातार दुःख-कष्ट से आये बदलाव की ओर भी संकेत करता है। सुनियोजित ढंग से इसे दबाने के हर प्रयास किए गये। इसे प्रतिक्रियावादियों की चाल बता कर बदनाम किया गया। सभी नेताओं को कैद कर लिया गया। सीआईटीयू के नेताओं को मिसा के अन्तर्गत नजरबंद किया गया। नौजवान लड़कों और लड़कियों को पुलिस ने पीटा और उन पर जुल्म किया। सभी बड़े शहरों पर अनियतकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया। जनता को दबाने के लिए सेना बुलाई गई। लगभग एक सौ लोगों को मार डाला गया।

किन्तु इन्दिरा सरकार प्रतिरोध की नई भावना को नहीं पहचान सकी। छात्र, कर्मचारी संगठन, राज्य कर्मचारी सभी डटे रहे। जनता का क्रोध अत्याचार और शोषण की गद्दियों की ओर मुड़ गया। सम्पदा और शोषण का प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्थाओं पर जनता क्रोधित हुई। जनता के इस आक्रोश को सरकार ने लूट बताया।

खून की नदी बहा कर भी असफल होने और समूचे देश मे गुजरात के दमन के खिलाफ तीव्र प्रतिवाद शुरू हो जाने पर इन्दिरा सरकार को झुकना पड़ा और जनता के हाथो अपनी घोर पराजय स्वीकारनी पड़ी। जन-संघर्ष तथा विधायकों के इस्ताफा देने की वजह से कांग्रेस की अच्छे खासे बहुमतवाली विधान सभा भंग करनी पड़ी। यह अपने किस्म की पहली घटना है।

यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विजय है—सिद्धान्तों की विजय। जनता से पूरी तरह कटे हुए तथा भ्रष्टाचारके कीचड़ में गले तक डूबे हुए विधानमण्डल को कायम रखने का कोई अधिकार नहीं है। संविधान भले कुछ भी क्यों न बोलता हो। सिद्धान्तों की ध्वजा फहरी है। संसदीय पद्धति पर गेरसंसदीय ताकतों कीं विजय हुई है।

अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाने के मतदाताओं के अधिकार के उपयोग का यह जनप्रिय रास्ता है।

मार्च महीने में बिहार मे एकबार फिर इसी प्रकार की छात्र समितियों की ओर से जब प्रतिवाद और प्रदर्शन संगठित गये। इन पर पुलिस ने गोली चला कर २० आदमियों को मार डाला। एकबार फिर पटना सहित कई शहरों मे कर्फ्यू लगा दिया गया। जनता पर जुल्म ढ़ाये गये। जनता ने मन्त्रियों के घरों, सरकारी कार्यालयों, तथा सम्पत्ति और अत्याचार की गद्दियों पर आक्रमण करके बदला लिया।

यहाँ लेनिन को याद करना बेहतर होगा। "१९०५ की रूसी क्रान्ति एक बुर्जुआ-जनवादी क्रान्ति थी। इसमें बहुतेरी लड़ाइयाँ लड़ी गईं जिनमें जनता के सभी विक्षुब्ध वर्गों, ग्रुपों और लोगों ने हिस्सा लिया। इनमें एसी जनता भी थी जिसमे बहुत भोंड़े कुसंस्कार थे। संघर्ष के बारे मे बहुत ही सतही और विचित्र खयाल थे। इनमें ऐसे छोटे ग्रुप भी थे जिन्होंने जापानियों से रुपये लिए; इसमें सट्टेबाज और दुस्साहसवादी वगैरह भी थे। लेकिन वस्तुगत तौर से यह जन-आंदोलन जार के शासन की कमर तोड़ रहा था। इसी लिए वर्ग सचेत मजदूर इसका नेतृत्व कर रहे थे।" (लेनिन-संकलित समग्र रचनावली, अंग्रेजी, खंड २२, पृ० ३५६)।

खाद्यान्न और महँगाई व वेकारी विरोधी बढ़ते हुए संघर्ष की इस पृष्ठभूमि में जन आन्दोलन ने समाजके व्यापकतम हिस्से को समेट लिया है। संगठित ट्रेड यूनियन आन्दोलन को इसमें अगुवाई और पथ-प्रदर्शक का काम करना होगा। उसे देखना होगा कि आन्दोलन जनवादी दिशा में चालित ही। इसमें असफलता अर्थ का होगा आन्दोलन को स्वत-स्फूर्त सचेतनता या लफ्फाजी करनेवाले प्रतिक्रियावादियों के हाथों में सौंप देना।

नया बजट

कामरेड, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा पेश किये गये बजटों से साफ जाहिर होता है कि महँगाई और अन्न की कमी से कोई मुक्ति नहीं है। पूँजीपति और जमींदार वर्ग के हितों में आर्थिक अव्यवस्था ने देश की अर्थव्यवस्था को सत्यानाश के कगार पर ला पटका है। पूँजीवादी देशों में चल रही मुद्रास्फीति के संकट से हमारी अर्थव्यवस्था जुड़ी होने के कारण यहाँ की स्थिति और बिगड़ती जा रही है। तेल के दामों में वृद्धि ने विदेशी मुद्रा के संकट को और गहरा कर दिया है। देश के जमींदारों के अन्न भण्डार पर काबू न कर पाने की वजह से हमें अनाज बाहर से मँगाना पड़ता है। दुनिया में अनाज के अत्यधिक दाम होने के कारण विदेशी मुद्रा के अस्थिर साधनों पर अत्यधिक भार पड़ रहा है तथा इससे देश को अधिक से अधिक विदेशी कर्ज की भीख मांगनी पड़ती है जिससे परनिर्भरता और बढ़ती है। स्वावलम्बन की लम्बी-चौड़ी बात हवा हो गयी हैं। विश्व बैंक ने भारत की दुर्दशा को जानकर उसके दिवालियेपन का विज्ञापन किया है तथा यह घोषणा की है कि भारत को पांच वर्ष के समय के लिये १२१० करोड़ डालर के कर्ज की आवश्यकता होगी जबकि योजना बनानेवालों ने इस काल के ५०० करोड़ डालर के कर्ज अनुमान किया था।

अर्थात सिर्फ मँहगाई, अन्न का अकाल और बड़े पैमाने पर बेकारी ही नहीं बल्कि कांग्रेसी शासन ने और विदेशी कर्ज के दैत्य तथा विदेशी आर्थिक प्रभुत्व के खतरा को भी पैदा कर दिया है। मँहगाई के खिलाफ अपनी जिन्दगी के लिये अब तक लड़ रहे मजदूर वर्ग और जनता को इसका सामना करना पड़ रहा है। जब तक मजदूर उन नीतियों को परास्त करने में सफल नहीं होता जिनसे मुद्रास्फीति पैदा होती है तथा आर्थिक निर्भरता के खिलाफ लड़ने के लिये तैयार नहीं होता, तब तक अब अधिक मँहगाई भत्ते के लिये लड़ाई बेमानी हो गई है।

बेकारी

कामरेड, मुद्रास्फीति के खिलाफ संघर्ष ने देश के सामने बड़े पैमाने पर मौजूद बेकारी के प्रश्न को भी ला खड़ा किया है। रजिस्टरशुदा शहरी बेकारों की संख्या ८२ लाख पहुँच गई है। गांवों में बेकारों की संख्या ढाई करोड़ से अधिक पहुंच गई है। फिलहाल शिक्षित बेकार ४० लाख हैं। १९७३ के जून महीने तक संख्या ३५ लाख थी। १९७२ के जून महीने से लेकर १९७३ के जून महीने के बीच रजिस्टरशुदा बेकारों की संख्या में ३३.५ फीसदी वृद्धि हुई है। समूचे देश को कंगाल बनाया जा रहा है।

जब तक काम करने का अधिकार या इसके पहले तक बेकारी भत्ते को वैज्ञानिक तौर पर हासिल नहीं किया जाता, तब तक जनता की कोई सुविधा, कोई राहत नहीं मिल सकती।

पिछले वर्ष, १९७३, के दौरान थोक मूल्यों का सरकारी सूचकांक २७ सैकड़ा बढ़ा है जबकि फुटकर बाजार में जिन्दगी की जरूरी चीजों के दाम ५० से ७० सैकड़ा तक बढ़े हैं तथा कुछ मामलों में तो दाम दूना हो गया है।

अनाज, चीनी, तेल, वनस्पति, मछली, दूध, ईंधन जैसी जिन्दगी की हर चीज आम आदमी की पहुंच के बाहर चली गयी है। पुरजोर बढ़ रही मुद्रास्फीति तथा इसके साथ ही साथ हर चीज की कामोबेश कमी से जनजीवन पूरी तरह से जमींदारों, अनाज के सट्टेबाजों, कालाबाजारियों की मुट्ठी में चला गया है। इनके खिलाफ कुछ करने की सरकार की हिम्मत नहीं होती क्योंकि यही सरकार के संरक्षकों में हैं। पिछले दो वर्षों में आम चीजों के दाम में ४२ प्रतिशत वृद्धि हुई है तथा अनाज के दाम में ४७ प्रतिशत।

१९७४-७५ के बजट में १२५ करोड़ रुपए का घाटा कूता गया है।

यह हास्यास्पद स्तर तक कम आंका गया है। इसमें अनाज में घाटा पूर्ति जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों को मनमाने तरीके से कम बताया गया है।

इसलिए इसमें जरा भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अखिल भारतीय उपभोक्ता कौंसिल के एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बजट पेश करने के १० दिनों के भीतर ही जनता के काम में आनेवाली चीजों के फुटकर दाम २० से ५० फीसदी तक बढ़ गये जबकि अब तक नये कर प्रस्तावों का लागू होना तो बाकी ही था।

बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मुद्रास्फीति विरोधी बताया जाये। इसमें असली घाटे को छिपाया गया है; किरासन जैसी आम खपत की बहुतसी चीजों पर कर बढ़ाये गये हैं; कोयला सहित प्रायः सभी माल रेलवे माशूल तथा तीसरे दर्जे के किराये सहित यात्रियों के किराये में वृद्धि की गई है। इसके अलावा राज्य सरकारों ने भी २५० से ३०० करोड़ के नये टैक्स लगाये हैं।

जहां एक ओर नये करों से जनता का खून चूसा जा रहा है वहीं बजट में धनियों को छूट दी गयी है। टैक्स में चोरी को रोकने के बहाने बड़े लोगों की व्यक्तिगत आमदनी पर आयकर को काफी घटाया गया है।

जमींदारों की चापलूसी

राज्यों के बजट में और केन्द्रीय बजट में जनता को चूसने वाले जमींदारों पर किसी भी प्रकार का भार लादने की चेष्टा नहीं की गयी है।

जमींदारों के खिलाफ राजस्व सम्बन्धी के कोई कदम नहीं ही उठाया गया है बल्कि उनके अनाज के अतिरिक्त भण्डार की वसूली भी बिल्कुल असफल रही हैं। जनता को उनके भरोसे छोड़ दिया गया है। खरीफ की फसल की वसूली का ६५ लाख टन का मामूली लक्ष्य भी पूरा नहीं

किया जा सका। अब सरकारी तौर पर गेहूँ का सरकारीकरण समाप्त कर दिया गया है और सरकार १०० से ११५ रुपये प्रति क्वींटल में कालाबाजारी दरों पर राजी हो गई है। सरकार जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जमींदारों के अतिरिक्त भण्डार पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं करती। थोक व्यापार में सट्टेबाजी की छूट, ऊँची दरों को स्वीकृति तथा रबी की कम फसल—इन सबसे जनता की दुर्दशा और बढ़ेगी तथा अनाज उसकी पहुँच के बाहर चला जायेगा।

विदेशी कर्जों पर निर्भरता की ही वजह से सरकार को एस्सो जैसी विदेशी कम्पनियों को अधिग्रहण के नाम पर मुआवजे की मनमानी दर देने के लिए वाध्य होना पड़ता है।

ट्रेड यूनियन आन्दोलन के लिए यह जरूरी है कि वह विदेशी तेल कम्पनियां तथा अन्य इजारेदार कम्पनियों को बिना मुआवजे राष्ट्रीयकरण की मांग उठाये।

मजदूर वर्ग को यह बात अच्छी तरह समझानी चाहिए कि खाद्य-संकट जमीन पर जमींदारों की इजारेदारी का सीधा परिणाम है। और जब तक मजदूर इस इजारेदारी को समाप्त करने के लिए अथक संघर्ष नहीं चलाता और जमीन पर भूमिहीनों और खेत मजदूरों का अधिकार नहीं नहीं होता, तब तक उन्हें इसी प्रकार से भूख का सामना करना पड़ेगा। उनका भविष्य जमींदारों और सट्टेबाजों के भरोसे रहेगा। मौजूदा खाद्य संकट से निश्चितरूप से मजदूरों और किसानों का एक मजबूत गठबन्धन तैयार हो जाना चाहिये। यह गठबन्धन उन सभी लोगों की जमीन को बाहर निकालेगा जिनके पास १० एकड़ नम या २० से ३० एकड़ सूखी जमीन से अधिक जमीन होगी तथा इस जमीन को भूमिहीनों और खेतीहर मजदूरों में बाँट दिया जायेगा।

अन्न के स्टाक पर कब्जा करो

इसके साथ ही यह भी महसूस किया जाना चाहिए कि वास्तव में ऐसी कोई वजह नहीं हैं जिसके कारण लाखों लोगों को भूखों रहना पड़े। यह जमींदारों और थोक व्यापारियों के सामने समर्पण की नीतियाँ ही हैं जिसके कारण मँहगाई बढ़ रही है और लोग भूखों मर रहे हैं। जमींदारों के समूचे अतिरिक्त स्टाक पर कब्जा करना चाहिए। सरकार इसके लिये अधिक दाम नहीं देना चाहिये। किसानों को बढ़ावा देने के लिये अधिक दाम देना चाहिये। इससे सरकार के हाथों आवश्यक स्टाक आ जायेगा जिससे हर बालिग को रोज आधा किलो अनाज दिया जा सकेगा।

इसके साथ ही हमें जरूरत के स्थान पर मजूरी की मांग भी करनी चाहिये। जैसा कि आपने देखा है, मुद्रास्फीतिकारी कदमों ने महँगाई भत्ते को कोरे छल में बदल दिया है। जब तक आवश्यकता पर आधारित मजूरी की कोई निश्चित गारंटी नहीं मिल जाती तब तक मजदूर वर्ग की जीविका की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती। सरकार और उसके अनुचरगण ऐसा दिखावा करते हैं कि जैसे कि भारत की मौजूदा परिस्थितयों में यह मांग मनमानी है और वे मजदूरों को खेतिहर मजदूर का विरोधी बताते हैं। जमींदार इसे शहर बनाम गांव का प्रश्न बना रहे हैं क्योंकि वे इसे भली-भाँति जानते हैं कि शहरों में मजदूरों का आगे बढ़ता हुआ हर कदम खेतिहर मजदूरों को भी अपनी मांगे पेश करने के लिये प्रोत्साहित करेगा।

आवश्यकता पर आधारित मजूरी मजदूर वर्ग का प्राथमिक जनवादी अधिकार है। इसीसे वह मुद्रास्फीति के आघात के सामने खुद की रक्षा कर सकता है और मजदूर वर्ग जितना ही इस माँग के करीब जायेगा उतना ही इस व्यवस्था का, जिसका आर्थिक स्तर पुराने औपनिवेशिक स्तर पर आधारित है, पतन भी करीब आता जायेगा।

इन परिस्थितियों के खिलाफ केरल से लेकर बंगाल तक, बंगाल से बम्बई और पंजाब तक मजदूर एक के बाद एक संघर्ष छेड़ रहे हैं। तमिलनाडू और बम्बई के कपड़ा मजदूरों की हड़ताल, कलकत्ते की चटकल मजदूरों की हड़ताल, केरल, तामिलनाडु और अन्य राज्यों के खेतिहर मजदूरों की हड़ताल, लोको और अन्य रेल मजदूरों की हड़ताल—इनसे मजदूर वर्ग की लगातार क्रियाशीलता जाहिर होती है।

रेल मजदूरों के विभिन्न हिस्सों के बीच उभर रही सीधी कार्रवाई की भावना हड़ताली संघर्षों का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस दौरान लोको मजदूरों को तीन बार हड़ताल करनी पड़ी।

एन० एफ० आर० में व्यवस्थापकों द्वारा वादा-खिलाफी के विरुद्ध लोको मजदूरों का संघर्ष तथा रेलवे गार्डों का संघर्ष रेल मजदूरों में संघर्ष की भावना के बिल्कुल ताजे उदाहरण हैं।

मँहगाई के खिलाफ तथा निम्नतम आर्थिक अधिकारों के लिए आन्दोलनमें सभी शामिल हुये। अराजपत्रित सरकारी, कर्मचारी जीवन-बीमा कर्मचारी, इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारी, डाक्टर, इन्जीनियर, प्रोफेसर तथा शिक्षकों ने काम बन्द कर दिया। सरकार को विच्छिन्न कर दिया गया। प्रायः कई जीते और प्रगति हासिल हुई।

इन संघर्षों के दौरान उभरती एक नई तस्वीर को पहचान जाना चाहिये तथा ट्रेड यूनियन आन्दोलन को एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ना चाहिये। पूँजीपतियों द्वारा मनमाने ढंग से लाक-आउट का इस्तेमाल करने के ही कारण प्रायः मजदूर वर्ग के संघर्ष लम्बे समय तक चलनेवाले रहे हैं और श्रम दिवस नष्ट हुए हैं।

२१ मार्च को पश्चिम बंगाल के श्रममंत्री डा० गोपालदास नाग ने राज्य विधान सभा में १९७३ में काम बन्द होने के बारे में कहते हुए कहा कि श्रम दिवस नष्ट होने काएक बढ़ता हुआ रुझान रहा है और अधिकांश

में लॉक-आउट के द्वारा व्यवस्थापकों के आक्रामक कदमों से बन्द हुआ है। उन्होंने कहा कि व्यवस्थापकों द्वारा समझौतों और फैसलों को लागू न करने के कारण ३४५,४८० श्रमदिवस बर्बाद हुये हैं।

सरकार मालिकों की नकल करती है

हाल ही में यह देखने को आया है कि सरकार ने सबसे रद्दी मालिकों की नकल करना शुरू कर दिया है। सरकार ने भी मजदूरों को भूख के सामने समर्पण करने के लिए लाक-आउट के तरीकों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में निजी मालिकों की तरह ही लाक-आउट कर दिया गया। यह मजदूरों की मजूरी खा गया। भूख के दवाब से कर्मचारियों को अलग-अलग अपने सभी ट्रेड यूनियन अधिकारों के समर्पण के लिए वाध्य होना पड़ा। उन्हें मजदूरों की जिन्दगी से मनमाना वर्ताव करने के व्यवस्थापकों के दावे को स्वीकार करना पड़ा जैसे कि मजदूर कोई जानवर हों।

जीवन बीमा में भी यही तरीके अपनाए गये। सैकड़ों जगह लाक आउट किया यया तथा संशोधनवादियों जैसे लोगों में से सरकार के श्रम लेफ्टिनेंटों का मजदूरों के प्रतिरोध को तोड़ने में प्रयोग किया गया।

आई ए सी के अधिकारियों ने यूनियन से समझौते की जिन शर्तों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा है उसमें कुछ भी अनकहा नहीं है।

समझौते के मेमोरंडम में मांग की गयी है कि मजदूर सांविधानिक तरीके इस्तेमाल करने तथा आन्दोलनात्मक और या योजनावद्ध कार्रवाइयों या अन्य किसी भी तरीकों को त्यागने पर सहमत हैं। जिससे कारपोरेशन के काम इत्यादि में बाधा या रुकावट पैदा न हो।

यह उस समय मांग की जा रही है जब संविधान में मूलभूत अधिकारों की अब तक खत्म नहीं किया गया है। अगर ट्रेड यूनियनें आंदोलन न कर सकें, यदि आप योजनावद्ध निर्णय और कार्रवाई न कर

सकें और अगर अब सौदेबाजी न कर सके तो फिर ट्रेड यूनियनों में बाकी रह ही क्या जाता है। आन्दोलन कब से गैरकानूनी हो गये? यह सभी प्रचार, आंदोलन, हड़ताल को बन्द करने की माँग है। इनका कहना हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने मामले को यूनियन में अपने साथी मजदूरों के साथ नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग पेश करे।

ऐसे दृष्टिकोण के साथ अधिकारी मजदूरों की काम कीं स्थिति को बदलने का निरंकुश अधिकार चाहते हैं। स्मरणपत्र में कहा गया है कि "मजदूर इसे स्वीकार करें कि व्यवस्थाधिकारियों के कुछ मूलभूत कार्य हैं जो नीचे बताये गये हैं" :—

व्यवस्थापक समय-समय पर प्रत्येक कैटेगरी के मजदूरों के कार्यों और जिम्मेदारियों को तय कर देंगे तथा मजदूर इन कार्यों को पूरा करेंगे—पदों की संख्या तथा उनके अधिकार दोनों सहित संस्थान की राशि व्यवस्थापक तय करेंगे—व्यवस्थापक उसी समय किसी कर्मचारी की पदोन्नति करेंगे जब कोई ऊँचा स्थान खाली हो तथा वह भी श्रेष्ठता और उपयुक्तता के अनुसार होगा।

किसी भी मजदूर को अपने अधिकार के रूप में छुट्टी नहीं मिलेगी। इसके लिये आवश्यक अधिकारी की अनुमति जरूरी है। एक आर्थिक वर्ष में विशेष छुट्टियां तीन बार से अधिक नहीं मिलेंगी। किसी भी मजदूर को अधिकारी जब मन में आये उचित कारण की नोटिश देकर विशेष छुट्टी दे सकता है। यदि मजदूर उस छुट्टी का उपभोग नहीं करता हैं तो उसकी छुट्टी खत्म हो जायेगी तथा उसकी छुट्टियों के हिसाब में उसे कम कर दिया जायेगा।

इसके बाद ट्रेड यूनियन और सामूहिक सौदेबाजी में क्या बचा रह जाता है? सरकार मिथ्या दिखावा करते हुए व्यवस्थापन में मजदूरों की भागीदारी की लफ्फाजी करती है जबकि उसके नियुक्त अधिकारी

सभी ट्रेड यूनियन अधिकारों तथा संगठित आन्दोलन को गैरकानूनी करने के हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं।

ट्रेड यूनियन आन्दोलन इस हमले को सफल नहीं होने दे सकता। यह शीघ्र ही अन्य सरकारी क्षेत्र के कारखानों की यूनियनों तथा फिर निजी क्षेत्र के मजदूरों पर भी लागू किया जायेगा।

नया बिल

इस परिस्थिति में नये श्रम सम्बन्ध बिल के वादों को कितनी मान्यता दी जा सकती जिसकी कापी श्रममन्त्री ने व्यापारी अधिकारियों को भेजी है कि सन्तुीआईटीयू को नहीं भेजी।

यदि अखबारों की खबरों को कोई इशारा माना जाए, तो इस बिल में स्वीकृति, पंजीकरण, पंचायती तथा एक उद्योग में एक यूनियन की चेष्टा के नये प्राविधान हैं। हमें बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए कि सरकार का इन नारों से क्या मतलब है। हमें जो बताते हैं, खुद वहीं नहीं समझते। सरकार मजदूरों के प्रश्न को मुख्यतः कानून व्यवस्था का प्रश्न समझती है। यही उनकी मूलभूत धारणा है। इनका हर प्रयास मजदूरों को नियन्त्रण में रखने का होता है। यह बात हम रोज देखते हैं जब मजदूर वर्ग के संघर्षों पर भारत रक्षा कानून तथा मिसा का प्रयोग किया जाता है और हड़ताल के दौरान मजदूरों की हत्या की जाती है।

जब सरकार और उसके प्रवक्ता एक उद्योग में एक यूनियन की बात करते हैं तो उनका सिर्फ यही मतलब रहता है कि उनके द्वारा मान्यताप्राप्त या शासक वर्ग अथवा उसके सहयोगियों के निमन्त्रण की यूनियन के अलावा दूसरी किसी भी यूनियन का अस्तित्व नहीं रहे। रेलवे में उनकी जिद में यही दिख रहा है। वे उस समय तक अपनी बात पर अड़े रहे जब तक कि बार-बार हड़ताल करके उन्हें बाध्य नहीं कर दिया।

गया कि तो उनके द्वारा स्वीकृत यूनियन के अलावा किसी भी यूनियन से बात कर सकते हैं। इसीलिए सरकार कभी भी मजदूरों के वास्तविक मत को स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन फिर भी वह उस समय तक जांच के अधिकारों का दावा करती रहेगी जब तक कि उसकी समर्थित यूनियन का पलड़ा भारी न हो जाय। ऐसा करके फिर तो यह मांग करेंगे, कि अब कोई दूसरी यूनियन नहीं चल सकती है, या उसे स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। एक उद्योग में एक यूनियन की बात उस समय तक बेकार है जब रक कि यूनियनें जनवादी रास्ता नहीं अपनातीं तथा वह मालिकों और सरकार की मर्जी पर निर्भर न रह कर मजदूरों की स्वतंत्र इक्छा पर आधारित है।

बहु यूनियनों की कठिनाइयों से बचने के नाम पर ट्रेड यूनियन आन्दोलन पर नये प्रतिबन्ध लगाने के सभी प्रयास विफल होंगे। मजदूरों के बुनियादी सांगठनिक अधिकार तथा अपनी मांगों को लागू करवाने के लिये अपनी अपनी इच्छा का औजार गढ़ने के उनके अधिकार पर किसी भी प्रकार का आघात ऐसे सभी कारनामों के उत्तर के तौर पर मजदूरों के असंतोष और गुस्से को और अधिक बढ़ायेगा। ईमानदारीपूर्ण तरीका यह है कि नरम यूनियन नेताओं का इस्तेमाल मजदूरों के बीच फूट पैदा करने में न जाय, उन यूनियनों से बातचीत की जाए जिन्हें वास्तव में मजदूरों का समर्थन प्राप्त है। इसी से सभी सच्चे तथा जनवादी तरीके से काम करनेवाले संगठन तेजी से करीब आयेंगे तथा वे सब मिलकर एक उद्योग में एक यूनियन का गठन करेंगे, अर्थात् ऐक उद्योग में सौदेबाजी के लिए एक यूनियन होगी। भारत की मजदूर परिस्थितियों में, जहां आवश्यकता पर आधारित मजूरी जैसा बुनियादी सिद्धान्त भी नहीं माना गया है, अन्य बातों को छोड़ कर इसे समझा जाना चाहिये। जब प्रत्येक मजदूर को एक निम्नतम मजूरी की गारंटी नहीं है तथा इसी आधार पर मजूरी में विषमता रहती है, ऐसी अवस्था

में भिन्न-भिन्न हिस्सों की विशेषता तथा स्थानीय परिस्थितियां मजबूत होती है और उसीके अनुरूप सांगठनिक ढांचा तैयार होगा।

नये संघर्ष

कामरेड, हम विशाल ट्रेड यूनियन आन्दोलन के बीच से गुजर रहे हैं। ९ अप्रेल को ४० लाख राज्य सरकारी कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगों के प्रति न्याय न किये जाने के विरोध में एकजुट एक दिन की की हड़ताल करेंगे राज्य कर्मचारियों की स्थिति केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के अनुरूप स्थितियां सहित अन्य मांगे बिल्कुल वाजिब हैं तथा हमारा सीआईटीयू उनका पूरा समर्थन करता है। यह ख्याल किया जाना चाहिये कि जनता के हिस्से के रूप में कर्मचारियों ने उचित मूल्य पर जनता को अनाज की नियमित सप्लाई के बल पर बल डाला है।

रेल हड़ताल

कामरेड, दूसरी महत्वपूर्ण घटना प्रस्तावित रेल हड़ताल है। यह हड़ताल होने पर ट्रेड यूनियन संघर्ष में यह ऐतिहासिक घटना होगी तथा यह मजदूरों के सभी हिस्सों के संघर्ष को अत्यधिक बल पहुंचाएगी। इससे जनवादी आन्दोलन भी आगे की ओर एक छलांग लगायेगा।

रेल मजदूरों की स्थितियां इतनी भयंकर हैं कि काफी पहले ही हड़ताल होनी चाहिए थी। किन्तु विश्वासघाती सुधारवादी नेतृत्व के कारण जिसका अब तक फेडरेशन पर प्रभाव था, किसी प्रकार का प्रतिरोध खड़ा नहीं किया जा सका।

तनख्वाह तथा जीवन की परिस्थियों के मामले में रेल मजदूरों की अवहेलना की जाती रही है। दूसरे उद्योगों की तुलना में रेल मजदूरों की मजूरी काफी कम है। कई कैटेगरियों के निपुण, अर्द्ध निपुण या अत्यधिक निपुण लोगों को उतनी भी मजूरी नहीं मिलती है जितनी कि

अन्य व्यक्तिगत और सरकारी क्षेत्र के संगठित उद्योगों में निम्नतम मजूरी है।

इसके अलावा लोको कर्मचारियों की हड़ताल से यह भी पता चला कि लोको कर्मचारियों पर कितने अमानवीय काल के घंटे लादे जाते हैं। यह जानकर पूरा देश स्तम्भित रह गया। अन्य कई हिस्से में लोगों की भी किसी न किसी बहाने लम्बे समय तक काम करना पड़ता है।

ऐसी अवहेलनापूर्ण स्थितियों तथा वास्तविक वेतन में हो रही गिरावट के बावजूद रेल मजदूरों की उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ी है। इसे दर्शाने के लिये सरकारी प्रकाशन द्वारा "१९७३-७४ में रेलवे में कामों की समीक्षा" में पेश किते गये आंकड़े ही काफी हैं।

१९५०-५१	१२२
१९६०-६१	१४७
१९७०-७१	१८६
१९७१-७२	११३
१९७२-७३	२००

संक्षेप में १९५०-५१ से अब तक मजदूरों की उत्पादन क्षमता ६० प्रतिशत वृद्धि हुई है। प्रत्येक कर्मचारी पहले के बनिश्बत उत्पादन के में ५० फीसदी अधिक योगदान करता है। किन्तु उसकी वास्तविक मजूरी में गिरावट आई है। यही शोषित मजदूर की आवाज का तथाकथित इनाम स्कीम के अन्तर्गत वर्कशाप में भी इसी बढ़े हुये कार्यभार तथा कार्य के चूसे गये घंटों को पाया जा सकता है। वर्कशाप का मरम्मत उत्पादन १९५७-५८ में ३,३५,००० बड़ी लाईन में वैगन से बढ़कर १९७२-७३ में ४६९,५६२ बड़ी लाईन की वैगन इकाइयों के बराबर हो गया जबकि कर्मचारियों की संख्या १९५७-५८ में ११६,००० आदमियों से घटकर १९७२-७३ में १११,६३४ आदमी ही गई जिनमें से ६४,४४७ व्यक्तियों को चलायमान स्टाफ की मरम्मत के लिए रखा

गया है। इसका अर्थ यह है कि कर्मचारियों की संख्या में ६ प्रतिशत की कटौती होकर भी मजदूर पहले से ५० फीसदी अधिक उत्पादन करते हैं।

रेल मजदूर भूखों रखनेवाली मजूरी और शोषित श्रम की इन स्थितियों में तड़प रहे हैं। लेकिन स्वीकृत फेडरेशन के नेताओं ने मजदूरों हितों को सामने रखने से इन्कार कर दिया तथा हड़ताल तोड़क के रूप में काम किया। किन्तु स्थितियाँ असहनीय हो उठीं तथा मजदूरों का बड़ा हिस्सा इन दो फेडरेशनों से अलग होने लगा जो रेलवे बोर्ड के साथ हाथ मिलाकर काम कर रहे थे।

बढ़ते हुए असन्तोष को बदनाम करने तथा उसे कुचल देने के लिए दोनों रेलवे फेडरेशनों के नेतृत्व और रेलवे बोर्ड ने साठ-गांठ कर ली। किन्तु तब भीतर ही भीतर उबलता असन्तोष अखिल भारतीय रेल मजदूर फेडरेशन के सितम्बर महीने में हुये वार्षिक अधिवेशन में फैल गया। हड़शाल के वास्तविक आह्वान की एक मांग उठी। इसके साथ ही बदनाम हड़ताल तोड़कर पीटर अलवारेस को जो फेडरेशन का अध्यक्ष था, उसके पद से हटा दिया गया और उस पद पर जोर्ज फर्नान्डीज चुने गये।

हड़ताल के लिए एक प्रस्ताव पास किया गया तथा प्रतिनिधियों ने ने जनरल सेक्रेटरी की रिपोर्ट में एक संशोधन करवा कर यह पास किया गया कि ए० आई० आर० एफ० को सभी रेल संगठनों को एक साथ होने ने आह्वान की पहल करनी चाहिये।

अन्य संगठनों में भी कुछ पूर्वाग्रह और भटकाव थे। ए० आई० आर० एफ० के नेताओं के पिछले करनामों को देखते हुये तथा उनके संकीर्ण दृष्टिकोण के शिकार कई नेताओं इनसे अलग ही रहना .चाहा। किन्तु नीचे के तबके में उठी एकजुटता की मांग ने सभी प्रतिरोधों को तोड़ दिया और सभी ने २७ फरवरी को ए० आई० आर० एफ० के आह्वान पर दिल्ली में हुये सभी रेल संगठनों के सम्मेलन में भाग लिया।

सम्मेलन में आवश्यकता पर आधरित वेतन तथा तत्काल कम से कम २६०) रुपये की सुविधा देने की मांग के साथ ही कई फ़ौरी मांगों को रखते हुये प्रस्ताव पास किया गया। इसने बातचीत के लिये १० अप्रेल तक का समय बाँध दिया गया। एक को-आर्डिनेशन कमेटी बनाई गई जिसमें सभी संगठनों के प्रतिनिधि हैं। इसके अलावा एक छोटी से कार्य-कारिणी बनाई गई जिसमें सी० आई० टी० यू० सहित प्रत्येक संगठन के दो-दो प्रतिनिधि शामिल किये गये। इस कमेटी में हमारे प्रतिनिधि हैं—सी० आई० टी० यू० के खजान्ची का० समर मुखर्जी तथा जनरल कौंसिल के सदस्य का० नृसिंह चक्रवर्ती।

कई दशकों से रेल मजदूरों के बीच जो एकता कायम नहीं हो पा रही थी, उसका कायम होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक घटना है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि ऊपर के स्तर पर कायम हुई उस एकता को बिल्कुल नीचे तक ले जाने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है।

यह हमारे लिए बहुत ही संतोषजनक बात है कि हमारे सी आई टी यू के कामरेडों ने अपनी भूमिका अदा की तथा इसी एकता को ओर आगे बढ़ाने, क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों के खिलाफ लड़ने तथा विभेद जारी रखने के सुधारवादियों के प्रयासों पर विजय पाने का विराट और महत्वपूर्ण काम पूरा करेंगे।

केन्द्रीय सम्मेलन

एआईआरएफ के नेताओं ने सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की एकसूत्र कार्रवाई की सम्भावनाओ की खोज के लिए एक सम्मेलन का आहवान किया है।

ए आई आर एफ की पहल से उस कार्रवाई में एक नया उत्साह आ गया। आम वातावरण ऐसा था कि फेडरेशन तथा डाक-तार के

संशोधनवादी दल के ने भी सम्मेलन में भाग लिया तथा एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पर सहमत हो गये जिसमें "हड़ताल" शब्द का उल्लेख जरूर नहीं किया गया है। किन्तु सभी संगठनों से ए आई आर एफ द्वारा बांधी गई समय सीमा १० अप्रैल तक बातचीत पूरी कर लेने का आह्वान किया गया है, इस सर्वसम्मत प्रस्ताव से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को काफी सहयोग मिला है किन्तु अब भी यह प्रश्न है कि क्या डाक-तार का सुधारवादी तबका इस सम्मिलित कार्रवाई में अपनी पूरी ताकत लगायेगा या नहीं।

जो भी हो, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संगठन तथा उनके नेता पूरे मन से अपने आन्दोलन को रेल मजदूरों से एकसूत्र करने की चेष्टा कर रहे हैं। इससे सरकार को आवश्यकता पर आधारित वेतन तथा अन्य मांगों पर मजदूर वर्ग के तन्त तक सबसे बड़े आन्दोलन का सामना करना पड़ेगा।

यह एक सबसे महत्वपूर्ण घटना घटने जा रही है। सीआईटीयू और उसके सभी संगठन निश्चित रूप से रेल मजदूरों तथा केन्द्रीय कर्मचारियों के संघर्ष में अपनी समूची ताकत लगा देगा। अपने दैनिक प्रचार और आन्दोलन में हमारी यूनियनों को इस विराट तबके को पूरी सहायता करनी चाहिए तथा उसके साथ एकजुटता जाहिर करने की सभाएँ करनी चाहिए और जन्ता को इनकी मुनासिब मांगों के बारे में शिकायत करना चाहिए। इसे निश्चित श्रम से मजदूरों के सभी हिस्सों को उनके पीछे रहने तथा दमनकारी कार्रवाइयों के खिलाफ सरकार को चेतावनी देने के लिए आह्वान करना चाहिए।

सी आई टी यू के हिन्दी प्रकाशन

१	भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र का संविधान	....	४० पैसा
२	संयुक्त ट्रेड यूनियन आन्दोलन की नयी दिशा—बी० टी० रणदिवे	....	४० पैसा
३	कर्मचारी परिवार पेन्शन योजना एक धोखा-घड़ी—एम के पंधे	....	२५ पैसा
४	तृतीय वेतन आयोग तथा रेल कर्मचारी— नृसिंह चक्रवर्ती	....	२० पैसा
५	सी०आई०टी०यू० का द्वितीय सम्मेलन सभापति का भाषण—बी० टी० रणदिवे	....	२० पैसा
६	सी०आई०टी०यू० का द्वितीय सम्मेलन साधारण रिपोर्ट—पी० राममूर्ति	...	२५ पैसा
७	मध्य प्रदेश में सी०आई०टी०यू० का आह्वान	....	२५ पैसा

मिलने का पता

१ भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र
१७१, लेनिन सरणी
कलकत्त-१३

२ नेशनल बुक एजेंसी
२२, बंकिम चटर्जी स्ट्रीट
कलकत्ता-१२